भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1350

दिनांक 06 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

टाइफाइड ज्वर और दवा प्रतिरोध विफलताओं की जांच

†1350. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः

श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2023 के दौरान देश में टाइफाइड ज्वर के लगभग 49 लाख मामलों और 7,800 से अधिक मौतों का अनुमान लगाने वाले 'द लैंसेट रीजनल हेल्थ' में प्रकाशित एक अध्ययन के निष्कर्षों का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश में टाइफाइड ज्वर के लगातार बढ़ते मामलों के लिए किन-किन कारणों की पहचान की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि देश में रिपोर्ट किए गए टाइफाइड के कुल मामलों का लगभग 30 प्रतिशत दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक से हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में लोक स्वास्थ्य नियोजन, स्वच्छता और रोगों की निगरानी में विशिष्ट विफलताओं का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) दशकों से एंटीमाइक्रोबियल के दुरुपयोग के संबंध में बार-बार चेतावनी दिए जाने के बाबजूद अस्पताल में भर्ती होने वाले लगभग 7.3 लाख लोगों में से लगभग छह लाख लोग सीधे तौर पर फ्लोरोक्विनोलोन रेजिस्टेंस की वजह से किस प्रकार भर्ती हुए; और

(च) क्या सरकार ने विशेषकर उच्च-भार वाले राज्यों में टाइफाइड ज्वर में एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध की सीमा का मूल्यांकन करने के लिए कोई स्वतंत्र राष्ट्रीय स्तर का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): उक्त अध्ययन भारत में 2023 में टाइफाइड बुखार और रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) के रोगभार पर एक मॉडल अध्ययन है, जिसमें भारत में आंत्र ज्वर निगरानी (एसईएफआई) अध्ययन (भारत में 6 महीने से 14 वर्ष की आयु के बच्चों में वर्ष 2017-2020 की अवधि के दौरान) से टाइफाइड बुखार की घटनाओं के आंकड़े, वैश्विक रोग भार अध्ययन 2021 और व्यवस्थित समीक्षाओं से राज्य-विशिष्ट एएमआर प्रसार डेटा (जिसमें उसी लेखक द्वारा संचालित टाइफाइड रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर वर्ष 2024 की व्यवस्थित समीक्षा प्रीप्रिंट भी शामिल है) को एकीकृत किया गया है। इस मॉडलिंग अध्ययन का उद्देश्य आयु, राज्य और एएमआर प्रोफाइल के

आधार पर वर्गीकृत करके वर्ष 2023 में भारत में टाइफाइड के रोगभार का अनुमान लगाना है; इसे नागासाकी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड-लीडिंग इन्नोवेटिव एंड स्मार्ट एजुकेशन (डब्ल्यूआईएसई) कार्यक्रम, वैक्सीन प्रभाव मॉडलिंग कंसोर्टियम और जापान चिकित्सा अनुसंधान और विकास एजेंसी द्वारा वित्त पोषित किया गया है। यह अध्ययन भारत सरकार द्वारा संचालित या वित्त पोषित नहीं किया गया है।
वर्ष 2023 में एकीकृत रोग निगरानी मंच-एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच (आईडीएसपी-आईएचआईपी) पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए टाइफाइड के मामलों का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ख) और (च): स्वास्थ्य राज्य का विषय है और रोगियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार की होती है। हालांकि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को प्राथमिक एवं माध्यमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रों को सुदृढ़ करने हेतु वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है, ताकि दूषित पेयजल के सेवन से उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याओं सहित स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी आवश्यकताओं का प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सके।

(ग): सरकार ने गौर किया है कि आईडीएसपी-आईएचआईपी पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की तुलना में दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक में अधिक मामले हैं। हालांकि, आईडीएसपी-आईएचआईपी के आंकड़ों के अनुसार, इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल मामले वर्ष 2023 में भारत के कुल मामलों के 20% से अधिक नहीं थे।

(घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) में एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) को टाइफाइड सहित कई महामारी-प्रवण रोगों की निगरानी का दायित्व सौंपा गया है। आईडीएसपी सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया गया है। निगरानी उपकरण में उप-केंद्र स्तर पर सहायक नर्स और मिडवाइफ (एएनएम) द्वारा भरा जाने वाला एस (सिंड्रोमिक) फॉर्म, स्वास्थ्य सुविधा केंद्र स्तर पर चिकित्सा अधिकारियों द्वारा भरा जाने वाला पी (प्रिजम्पटिव) फॉर्म और मानक केस परिभाषाओं के अनुसार प्रयोगशालाओं द्वारा भरा जाने वाला एल (प्रयोगशाला द्वारा पुष्ट) फॉर्म शामिल है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बाढ़ की घटनाओं के लिए व्यापक 'सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशानिर्देश' जारी किए हैं, जिनमें बाढ़ के कारण होने वाले सामान्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावों, बाढ़ के दौरान और बाद में रोगों की निगरानी, विशेष रूप से जल और खाद्य जनित रोगों, वेक्टर जनित रोगों पर विशेष फेकस करते हुए जल एवं स्वच्छता संबंधी मुद्दों आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। दिशानिर्देश का लिंक नीचे दिया गया हैः https://www.ncdc.mohfw.gov.in/wp-content/uploads/2024/08/PUBLIC-HEALTH-GUIDELINES-FOR-FLOOD-EVENT.pdf

इसके अलावा, ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों/जल समितियों के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता, नियमित जल गुणवत्ता परीक्षण, संवेदीकरण कार्यशालाओं, स्वच्छता और सफाई पर जन जागरूकता अभियानों, अतिसंवेदनशील समूहों के लिए लक्षित कार्यकलापों और सुरक्षित जल शोधन और हाथ धोने की प्रथाओं पर

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जलजनित रोगों की रोकथाम और सुरक्षित जल प्रथाओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दिया जाता है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।

(ङ): 1990 के दशक के उत्तरार्ध और 2000 के दशक के आरंभ से नालिडिक्सिक-एसिड-प्रतिरोधी और फ्लोरोक्विनोलोन-गैर-संवेदनशील साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी उपभेदों के व्यापक उद्भव के बाद आंत्र ज्वर के लिए नियमित अनुभवजन्य प्रथम-पंक्ति चिकित्सा के रूप में फ्लोरोक्विनोलोन पर भरोसा करना बंद कर दिया गया।
राष्ट्रीय एएमआर रोकथाम कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित एएमआर नेटवर्क की वार्षिक संक्रमण एएमआर निगरानी रिपोर्ट 2024 के अनुसार, भारत में फ्लोरोक्विनोलोन प्रतिरोधक क्षमता लगभग 33.5% है। इस प्रतिरोधक पैटर्न को देखते हुए, संक्रामक रोग सिंड्रोम में रोगाणुरोधी उपयोग के लिए राष्ट्रीय उपचार दिशानिर्देश वर्ष 2016, और बाद में वर्ष 2025 में, आंत्र ज्वर के लिए प्रारंभिक उपचार के रूप में सेफ्ट्रियाक्सोन और एज़िथ्रोमाइसिन की सिफारिश की गई है।

अनुलग्नक

2023 में आईडीएसपी के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एल-फॉर्म पर दर्ज किए गए टाइफाइड के मामले।		
क्र.सं	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	टाइफाइड के मामलों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	176
2	आंध्र प्रदेश	38747
3	अरुणाचल प्रदेश	4262
4	असम	11497
5	बिहार	33269
6	चंडीगढ़	734
7	छत्तीसगढ़	39536
8	दिल्ली	22969
9	गोवा	46
10	गुजरात	17851
11	हरियाणा	26434
12	हिमाचल प्रदेश	9194
13	जम्मू और कश्मीर	19244
14	झारखंड	11104
15	कर्नाटक	42096
16	केरल	1740
17	लद्दाख	25
18	लक्षद्वीप	41
19	मध्य प्रदेश	20862
20	महाराष्ट्र	46673
21	मणिपुर	816
22	मेघालय	11651
23	मिजोरम	15203
24	नागालैंड	5234
25	ओडिशा	23628
26	पुदुचेरी	1351
27	पंजाब	13268
28	राजस्थान	41269
29	सिक्किम	2201
30	तमिलनाडु	29920
31	तेलंगाना	20730
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	739
33	त्रिपुरा	6694
34	उत्तराखंड	11638
35	उत्तर प्रदेश	40375
36	पश्चिम बंगाल	2919
कुल		कुल

स्रोत: ***आईडीएसपी-आईएचआईपी पोर्टल से 22 जनवरी 2026 तक का डेटा उद्धृत।***

*****